IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 4 October-December, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.23540159

ISSN : 3048-6971

"डिजिटल मीडिया और राजनीतिक जनमत निर्माण: भारतीय संदर्भ में"

डॉ0 विनीता
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
हर्ष विद्या मंदिर (पी.जी) कॉलेज, रायसी, हरिद्वार (उत्तराखंड)

सारांश

वर्तमान डिजिटल युग में मीडिया राजनीतिक संचार और जनमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। विशेष रूप से सामाजिक मीडिया, समाचार पोर्टल, वीडियो मंच तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक सूचनाओं के प्रसार, नागरिक सहभागिता और राजनीतिक विमर्श की प्रकृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में डिजिटल मीडिया की राजनीतिक जनमत निर्माण में भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल माध्यम किस प्रकार नागरिकों को राजनीतिक सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं तथा नागरिकों को राजनीतिक संवाद और सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की संभावनाओं को भी बढ़ाया है। इसके माध्यम से राजनीतिक विचार, नीतियाँ, चुनावी मुद्दे और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ अपेक्षाकृत तेजी से व्यापक जनसमूह तक पहुँचती हैं। दूसरी ओर, फर्जी समाचार, भ्रामक सूचनाएँ, राजनीतिक ध्रुवीकरण, डिजिटल असमानता, निजता संबंधी चिंताएँ तथा लक्षित राजनीतिक प्रचार जैसी चुनौतियाँ जनमत निर्माण की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं। अध्ययन यह रेखांकित करता है कि डिजिटल मीडिया लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है, किंतु इसके प्रभाव को समझने के लिए सूचना की गुणवत्ता, नागरिकों की डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार राजनीतिक संचार को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः भारतीय लोकतंत्र में स्वस्थ एवं सूचित जनमत के निर्माण के लिए डिजिटल मीडिया के विवेकपूर्ण, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की आवश्यकता है।

मुख्य शब्दः डिजिटल मीडिया, राजनीतिक जनमत, राजनीतिक संचार, लोकतंत्र, नागरिक सहभागिता, सामाजिक मीडिया, डिजिटल साक्षरता, राजनीतिक जागरूकता, भारत।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीक के तीव्र विकास ने समाज, राजनीति और शासन की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप डिजिटल मीडिया आधुनिक राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। डिजिटल मीडिया से आशय ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट आधारित माध्यमों से है, जिनके द्वारा सूचना, विचार, समाचार, चित्र, वीडियो तथा अन्य सामग्री का निर्माण, प्रसारण और आदान–प्रदान तीव्र गति से किया जाता है। सामाजिक माध्यम, समाचार जालस्थल, ऑनलाइन चर्चा मंच, वीडियो आधारित मंच तथा विभिन्न प्रकार के डिजिटल संचार माध्यम इसके प्रमुख स्वरूप हैं। पारंपरिक मीडिया की तुलना में डिजिटल मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी तात्कालिकता, व्यापक पहुँच, पारस्परिकता और सहभागिता है। इसमें केवल सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं सूचना का निर्माण, प्रतिक्रिया और प्रसार भी कर सकता है। इस प्रकार डिजिटल मीडिया ने सूचना के प्रवाह को अधिक बहुआयामी बनाया है तथा राजनीतिक विचारों के निर्माण और प्रसार की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है।

भारतीय राजनीति में डिजिटल माध्यमों का महत्व पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ा है। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और नागरिक अब राजनीतिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग करते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक घोषणाओं, नीतिगत विचारों, नेताओं के वक्तव्यों और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को डिजिटल माध्यमों के द्वारा तेजी से जनता तक पहुँचाया जाता है। इससे राजनीतिक संचार की गति और क्षेत्र दोनों में विस्तार हुआ है। नागरिकों को विभिन्न राजनीतिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने, विचार साझा करने तथा सार्वजनिक बहस में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से युवाओं के बीच डिजिटल माध्यम राजनीतिक जानकारी प्राप्त करने और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं।

राजनीतिक जनमत से आशय किसी राजनीतिक मुद्दे, नीति, संस्था, नेतृत्व या सार्वजनिक प्रश्न के संबंध में नागरिकों के सामूहिक विचारों, धारणाओं और दृष्टिकोणों से है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शासन

और राजनीतिक संस्थाओं की वैधता काफी हद तक नागरिकों की धारणाओं और सहभागिता से जुड़ी होती है। डिजिटल मीडिया इस जनमत के निर्माण, परिवर्तन और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। किसी राजनीतिक घटना या मुद्दे से संबंधित सूचना जब व्यापक स्तर पर प्रसारित होती है, तो वह नागरिकों की धारणाओं को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, विभिन्न विचारों के बीच संवाद और बहस के माध्यम से राजनीतिक चेतना का विकास भी संभव होता है। इस प्रकार डिजिटल मीडिया और राजनीतिक जनमत के बीच गहरा अंतर्संबंध स्थापित होता है। हालांकि, भ्रामक सूचना, अफवाह और पक्षपातपूर्ण सामग्री जनमत को प्रभावित करने की चुनौती भी उत्पन्न करती है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में डिजिटल मीडिया की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक जनमत की प्रकृति, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक संचार को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल मीडिया का विकास और भारतीय राजनीति

भारत में डिजिटल मीडिया का विकास सूचना एवं संचार तकनीक के विस्तार के साथ हुआ है और पिछले दो दशकों में इसने राजनीतिक संचार की प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया है। प्रारम्भिक दौर में इंटरनेट मुख्यतः सूचना प्राप्त करने और संचार के सीमित साधन के रूप में प्रयुक्त होता था, किंतु धीरे–धीरे सामाजिक माध्यमों, ऑनलाइन समाचार माध्यमों, वीडियो मंचों और संदेश–आधारित सेवाओं के विस्तार ने इसे सार्वजनिक संवाद का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया। डिजिटल माध्यमों की विशेषता यह है कि इनमें सूचना का निर्माण और प्रसार केवल पारंपरिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामान्य नागरिक भी अपनी राजनीतिक धारणाओं, प्रतिक्रियाओं और विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार सूचना का प्रवाह अधिक सहभागी और बहुआयामी हुआ है। बीजू पी. आर. ने डिजिटल इंटरनेट को भारतीय संदर्भ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक विमर्श और सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा है। उनके अनुसार इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों ने सार्वजनिक क्षेत्र की पारंपरिक सीमाओं का विस्तार किया है तथा नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों और प्रतिरोध के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।[i]

भारत में सामाजिक मीडिया मंचों के विस्तार ने राजनीतिक संचार को और अधिक व्यापक बनाया है। सामाजिक माध्यमों ने राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिकों के बीच संवाद की ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसमें सूचना का प्रसार बहुत कम समय में बड़े जनसमूह तक किया जा सकता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे माध्यमों ने राजनीतिक विचारों, चुनावी संदेशों, सार्वजनिक अभियानों और सामाजिक आंदोलनों को व्यापक दृश्यता प्रदान की। शालिनी चोपड़ा के अध्ययन में भारतीय राजनीति में सामाजिक मीडिया के प्रभाव, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसके प्रयोग तथा 2014 के आम चुनावों में इसके उपयोग का विश्लेषण किया गया है। वह दिखाती हैं कि सामाजिक मीडिया ने राजनीति और जनसंचार के बीच संबंधों को नए रूप में स्थापित किया तथा युवाओं सहित विभिन्न सामाजिक समूहों तक राजनीतिक संदेश पहुँचाने की क्षमता बढ़ाई।[ii]

राजनीतिक संचार में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग केवल सूचना प्रसारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक संवाद, प्रतिक्रिया, सहभागिता और जनमत निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ गया है। राजनीतिक नेता अपने विचारों, नीतियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सीधे नागरिकों तक पहुँचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नागरिक भी राजनीतिक संदेशों पर प्रतिक्रिया देकर, उन्हें साझा करके और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं। शेख मोइनुद्दीन ने भारतीय राजनीतिक ट्विटर क्षेत्र के अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि राजनीतिक नेताओं द्वारा किए जाने वाले संदेशों और पुनःप्रसारणों ने राजनीतिक संवाद, सक्रियता और डिजिटल राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया है।[iii]

राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा डिजिटल मीडिया का उपयोग विशेष रूप से चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। राजनीतिक दल डिजिटल माध्यमों के द्वारा अपने कार्यक्रमों, घोषणाओं और राजनीतिक विचारों को मतदाताओं तक पहुँचाते हैं तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का प्रयास करते हैं। डिजिटल माध्यमों के कारण राजनीतिक अभियान केवल रैलियों और पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ऑनलाइन संवाद, सामाजिक मीडिया अभियान और डिजिटल सामग्री के माध्यम से भी संचालित होने लगे हैं। अनिकेत लाल ने भारत में सामाजिक मीडिया के राजनीतिक उपयोग का अध्ययन करते हुए इसके राजनीतिक अभियानों, आंदोलनों और नागरिक सक्रियता पर प्रभाव को रेखांकित किया है।[iv] वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक संचार पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों के संयोजन की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन ने राजनीतिक भागीदारी और जनमत निर्माण के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, लेकिन इसके साथ सूचना की विश्वसनीयता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और भ्रामक सूचनाओं जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। हाल के अध्ययनों में भी भारतीय राजनीतिक संचार में डिजिटल माध्यमों के कारण चुनावी अभियान, मतदाता सहभागिता और सार्वजनिक विमर्श में आए परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है।

राजनीतिक जनमत निर्माण में डिजिटल मीडिया की भूमिका

1. **राजनीतिक सूचनाओं के प्रसार में भूमिका–** डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक सूचनाओं के प्रसार की पारंपरिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया है। पहले राजनीतिक सूचनाओं के लिए समाचार–पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तथा राजनीतिक सभाओं पर अधिक निर्भरता थी, जबकि वर्तमान समय में नागरिक इंटरनेट आधारित माध्यमों के द्वारा राजनीतिक घटनाओं, सरकारी नीतियों, चुनावी घोषणाओं, राजनीतिक नेताओं के वक्तव्यों तथा विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित सूचनाएँ तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों की विशेषता यह है कि सूचना का प्रसार केवल संस्थागत माध्यमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामान्य नागरिक भी किसी राजनीतिक घटना की सूचना, टिप्पणी अथवा दृश्य सामग्री को व्यापक स्तर पर साझा कर सकता है। इस प्रकार राजनीतिक सूचना का प्रवाह अधिक तीव्र, व्यापक और सहभागी हो गया है। शेठ, सुरेश ने भारतीय संदर्भ में सामाजिक माध्यमों की राजनीतिक क्षमता पर चर्चा करते हुए बताया है कि डिजिटल माध्यम राजनीतिक संचार को अधिक प्रत्यक्ष बनाते हैं और राजनीतिक संस्थाओं तथा नागरिकों के बीच संवाद के नए अवसर पैदा करते हैं।[v] राजनीतिक सूचना की यह व्यापक उपलब्धता नागरिकों को विभिन्न राजनीतिक विषयों पर अपनी समझ विकसित करने में सहायता करती है। हालांकि, डिजिटल माध्यमों पर सूचना की अत्यधिक मात्रा तथा अपुष्ट सामग्री की उपलब्धता के कारण नागरिकों के सामने विश्वसनीय सूचना की पहचान करने की चुनौती भी रहती है।

2. **नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता–** राजनीतिक जनमत के निर्माण के लिए नागरिकों का राजनीतिक रूप से जागरूक होना आवश्यक है। डिजिटल मीडिया नागरिकों को राजनीतिक संस्थाओं, संविधान, अधिकारों, सरकारी योजनाओं, चुनावी प्रक्रियाओं तथा समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। नागरिक किसी विषय से संबंधित विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को पढ़ तथा सुन सकते हैं और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक समझ विकसित कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों ने विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए राजनीतिक जानकारी तक पहुँच आसान बनाई है जो पारंपरिक राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। चोपड़ा, शालिनी ने भारतीय राजनीति में सामाजिक मीडिया की भूमिका का अध्ययन करते हुए उल्लेख किया है कि सामाजिक माध्यमों ने राजनीतिक जानकारी के प्रसार तथा नागरिकों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवाद को अधिक प्रत्यक्ष बनाया है।[vi] इस प्रकार डिजिटल मीडिया नागरिकों को केवल राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने और अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

3. **राजनीतिक विमर्श एवं बहस को प्रभावित करना–** डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक विमर्श और सार्वजनिक बहस के स्वरूप को भी बदल दिया है। सामाजिक माध्यमों पर नागरिक, राजनीतिक नेता, पत्रकार, विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक संवाद अधिक तात्कालिक और सहभागी बन गया है। किसी राजनीतिक घटना या सार्वजनिक नीति पर नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ कुछ ही समय में व्यापक चर्चा का रूप ले सकती हैं। डिजिटल माध्यमों पर होने वाली टिप्पणियाँ, विचार–विमर्श और साझा की गई सामग्री राजनीतिक मुद्दों की सार्वजनिक दृश्यता को प्रभावित कर सकती हैं। मोइनुद्दीन, शेख ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक माध्यमों के अध्ययन में पाया कि डिजिटल मंचों ने राजनीतिक नेताओं और नागरिकों के बीच संवाद तथा राजनीतिक सक्रियता के नए रूपों को बढ़ावा दिया है।[vii] हालांकि, डिजिटल राजनीतिक विमर्श में विचारों का टकराव, राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा भ्रामक सूचनाएँ भी सार्वजनिक बहस की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल राजनीतिक विमर्श में तथ्यपरकता और जिम्मेदार अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है।

4. **युवाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देना–** डिजिटल मीडिया ने युवाओं को राजनीतिक सहभागिता के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। युवा सामाजिक माध्यमों के द्वारा राजनीतिक समाचार प्राप्त करने, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने, नेताओं से संवाद करने और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक अभियानों में भाग लेने में सक्षम हुए हैं। डिजिटल माध्यमों के कारण राजनीतिक सहभागिता केवल मतदान या राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष गतिविधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन चर्चा, सूचना साझा करने, जनअभियान और डिजिटल सक्रियता जैसे नए रूप भी सामने आए हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग करता है, जिसके कारण राजनीतिक सूचनाओं और राजनीतिक विचारों तक उसकी पहुँच अपेक्षाकृत अधिक सहज हुई है। नयाजी, तबरेज अहमद, कुमार, अनूप तथा सेमेटको, हॉली ए. ने भारतीय चुनावी राजनीति के अध्ययन में पाया कि सामाजिक माध्यमों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियाँ नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूपों से जुड़ी हुई थीं।[viii] इस प्रकार डिजिटल मीडिया युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

5. **जनसमर्थन एवं राजनीतिक मुद्दों के निर्माण में भूमिका–** डिजिटल मीडिया किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को व्यापक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी मुद्दे से संबंधित सामग्री बड़ी संख्या में लोगों द्वारा साझा की जाती है, उस पर प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की जाती हैं और लगातार चर्चा होती है, तो

उसकी सार्वजनिक दृश्यता बढ़ सकती है। राजनीतिक दल और नेता भी डिजिटल माध्यमों पर नागरिकों की प्रतिक्रियाओं तथा चर्चाओं को देखकर राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार डिजिटल माध्यम राजनीतिक मुद्दों की पहचान, उनकी चर्चा तथा जनसमर्थन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कानूंगो, नीना तलवार ने भारतीय चुनावी राजनीति के संदर्भ में सामाजिक मीडिया को राजनीतिक मुद्दों और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक विमर्श के निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा है।[ix] इस प्रकार डिजिटल मीडिया जनमत का केवल प्रतिबिंब प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि राजनीतिक मुद्दों की दृश्यता, प्राथमिकता और सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित करने वाली सक्रिय भूमिका भी निभाता है। फिर भी यह आवश्यक है कि डिजिटल माध्यमों पर बनने वाले जनमत को व्यापक समाज के समग्र जनमत का पूर्ण प्रतिनिधि न माना जाए, क्योंकि डिजिटल पहुँच, तकनीकी ज्ञान और सूचना तक पहुँच में सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ विद्यमान हैं।

डिजिटल मीडिया और राजनीतिक संचार

1. **राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद–** डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक संचार की पारंपरिक व्यवस्था को अधिक प्रत्यक्ष, त्वरित और सहभागी बनाया है। पहले राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच संवाद मुख्यतः सार्वजनिक सभाओं, राजनीतिक रैलियों, समाचार–पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे माध्यमों से होता था। डिजिटल माध्यमों के विस्तार के बाद राजनीतिक दल और नेता नागरिकों तक अपने विचार, नीतियाँ और कार्यक्रम सीधे पहुँचा सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक भी राजनीतिक नेताओं और दलों को अपनी प्रतिक्रियाएँ, प्रश्न तथा सुझाव सीधे भेज सकते हैं। इससे राजनीतिक संचार में मध्यस्थता की भूमिका कुछ हद तक कम हुई है और संवाद की प्रक्रिया अधिक निरंतर बनी है। चोपड़ा, शालिनी ने भारतीय राजनीति में सामाजिक माध्यमों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए बताया है कि सामाजिक मीडिया ने राजनीतिक नेताओं को नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने तथा राजनीतिक संदेशों को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के नए अवसर प्रदान किए है।[x] इस प्रकार डिजिटल मीडिया राजनीतिक संचार को एकतरफा प्रचार के बजाय संवादात्मक प्रक्रिया में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है।
2. **चुनावी अभियानों में डिजिटल मीडिया–** चुनावी राजनीति में डिजिटल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ा है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र, नीतिगत विचार, उम्मीदवारों की जानकारी और चुनावी कार्यक्रमों को नागरिकों तक पहुँचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं। डिजिटल माध्यम चुनावी अभियान को भौगोलिक सीमाओं से आगे ले जाने में सहायता करते हैं और राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों तक अलग–अलग प्रकार की सामग्री पहुँचा सकते हैं। भारत में चुनावी अभियानों के संदर्भ में सामाजिक मीडिया का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। नयाजी, तबरेज अहमद, कुमार, अनूप तथा सेमेटको, हॉली ए. ने 2014 के भारतीय आम चुनाव के अध्ययन में सामाजिक मीडिया आधारित राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंधों का विश्लेषण किया तथा पाया कि राजनीतिक अभियान में सामाजिक मीडिया का उपयोग नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव से संबंधित था।[xi] इस प्रकार डिजिटल मीडिया चुनावी संचार को अधिक व्यापक और निरंतर बनाने में सहायक है।
3. **राजनीतिक संदेशों एवं प्रचार का प्रसार–** डिजिटल माध्यम राजनीतिक संदेशों और प्रचार सामग्री के तीव्र प्रसार के लिए प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। राजनीतिक भाषण, घोषणाएँ, नीतिगत विचार, चुनावी अपील, वीडियो और अन्य सामग्री बहुत कम समय में बड़ी संख्या में नागरिकों तक पहुँच सकती है। डिजिटल माध्यमों की पारस्परिक प्रकृति के कारण नागरिक इन संदेशों को केवल प्राप्त ही नहीं करते, बल्कि उन्हें साझा, टिप्पणी और पुनःप्रसारित भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी राजनीतिक संदेश की पहुँच उसके मूल स्रोत से कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। मोइनुद्दीन, शेख ने भारतीय राजनीतिक ट्विटर क्षेत्र का अध्ययन करते हुए राजनीतिक नेताओं द्वारा डिजिटल मंचों के उपयोग को राजनीतिक संचार और सक्रियता के महत्वपूर्ण रूप के रूप में प्रस्तुत किया है।[xii] हालांकि, राजनीतिक संदेशों के तीव्र प्रसार के साथ भ्रामक सूचना, अपुष्ट दावे और अत्यधिक पक्षपातपूर्ण सामग्री के प्रसार की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए डिजिटल राजनीतिक प्रचार में तथ्यात्मकता और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हैं।
4. **डिजिटल माध्यमों से नागरिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना–** डिजिटल मीडिया राजनीतिक दलों और नेताओं को नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम उपलब्ध कराता है। नागरिक टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं, ऑनलाइन चर्चाओं और अन्य डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करते हैं। राजनीतिक संस्थाएँ इन प्रतिक्रियाओं से नागरिकों की प्राथमिकताओं, समस्याओं और राजनीतिक मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इससे राजनीतिक संचार केवल संदेश भेजने की प्रक्रिया न रहकर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया बन जाता है। उदूपा, साहना, वेंकटरमन, श्रीराम एवं खान, आसिम ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र का अध्ययन करते हुए यह रेखांकित किया है कि सामाजिक माध्यम नागरिकों को राजनीतिक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक सहभागिता के नए अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि इनके भीतर असहमति, संघर्ष और बहिष्करण की स्थितियाँ भी उत्पन्न हो

सकती हैं।[xiii] इस प्रकार डिजिटल मीडिया आधुनिक राजनीतिक संचार में सूचना, संवाद और प्रतिक्रियाकृतीनों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

डिजिटल मीडिया की चुनौतियाँ

1. **फर्जी समाचार एवं भ्रामक सूचनाएँ–** डिजिटल मीडिया के विस्तार ने राजनीतिक सूचना तक पहुँच को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ फर्जी समाचार और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार भी एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। डिजिटल माध्यमों पर कोई सूचना बहुत कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच सकती है और नागरिक उसे सत्यापित किए बिना आगे प्रसारित कर सकते हैं। राजनीतिक संदर्भ में किसी नेता के वक्तव्य, चुनावी घटना, सरकारी नीति या सामाजिक मुद्दे से संबंधित गलत सूचना नागरिकों की राजनीतिक धारणाओं को प्रभावित कर सकती है। वार्डल, क्लेयर तथा डेराखशन, होसैन ने गलत सूचना की समस्या का अध्ययन करते हुए बताया है कि डिजिटल वातावरण में झूठी अथवा भ्रामक सामग्री का प्रसार नागरिकों के सूचना संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।[xiv] भारतीय राजनीति में चुनावी समय में ऐसी सूचनाओं का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नागरिकों के राजनीतिक निर्णय बड़ी मात्रा में उपलब्ध सूचनाओं से प्रभावित होते हैं। अतः राजनीतिक जनमत निर्माण में डिजिटल मीडिया की भूमिका का अध्ययन करते समय सूचना की सत्यता और स्रोत की विश्वसनीयता को विशेष महत्व देना आवश्यक है।
2. **राजनीतिक ध्रुवीकरण–** डिजिटल मीडिया की दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती राजनीतिक ध्रुवीकरण है। डिजिटल मंचों पर नागरिक प्रायः ऐसे विचारों और सूचनाओं के संपर्क में अधिक आते हैं जो उनके पूर्वनिर्धारित राजनीतिक दृष्टिकोणों से मेल खाते हैं। परिणामस्वरूप समान विचार रखने वाले समूहों के भीतर विचारों की पुनरावृत्ति होती रहती है और राजनीतिक मतभेद अधिक तीव्र रूप ग्रहण कर सकते हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण लोकतांत्रिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि असहमति के बावजूद तर्कपूर्ण संवाद की संभावना कमजोर हो सकती है। सनस्टीन, कैस ने डिजिटल संचार के संदर्भ में ऐसे समूहों की चर्चा की है जहाँ समान विचारों वाले लोग एक–दूसरे के विचारों को और अधिक मजबूत करते हैं तथा इससे सार्वजनिक विमर्श में विभाजन बढ़ सकता है।[xv] भारतीय संदर्भ में भी राजनीतिक विचारों की तीव्र प्रतिस्पर्धा डिजिटल माध्यमों पर दिखाई देती है। इसलिए डिजिटल मीडिया का उपयोग लोकतांत्रिक बहस को व्यापक बनाने के साथ–साथ विभिन्न विचारों के बीच संतुलित संवाद स्थापित करने की दृष्टि से भी किया जाना आवश्यक है।
3. **सूचना की विश्वसनीयता की समस्या–** डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध राजनीतिक सूचनाओं की विश्वसनीयता एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। पारंपरिक समाचार माध्यमों में संपादन, स्रोत–जाँच और संस्थागत उत्तरदायित्व की प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत स्पष्ट होती हैं, जबकि डिजिटल मंचों पर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सामग्री तैयार करके उसे व्यापक स्तर पर प्रसारित कर सकता है। इससे तथ्य, राय, प्रचार और भ्रामक सूचना के बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। विशेष रूप से राजनीतिक विषयों पर भावनात्मक अथवा सनसनीखेज सामग्री नागरिकों का अधिक ध्यान आकर्षित कर सकती है। वार्डल और डेराखशन ने सूचना विकार की समस्या में गलत सूचना, दुष्प्रचार और दुर्भावनापूर्ण सामग्री के विभिन्न रूपों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।[xvi] इसलिए नागरिकों में डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता विकसित करना आवश्यक है।
4. **निजता एवं डेटा सुरक्षा–** डिजिटल राजनीतिक संचार के विस्तार के साथ नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल मंचों पर नागरिकों की गतिविधियों, रुचियों और व्यवहार से संबंधित बड़ी मात्रा में आँकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। राजनीतिक संचार में इन आँकड़ों के उपयोग से विशेष समूहों तक लक्षित राजनीतिक संदेश पहुँचाने की क्षमता बढ़ती है। इससे राजनीतिक संचार अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से न किया जाए तो नागरिकों की निजता प्रभावित हो सकती है। कैडवालाडर, कैरोल ने राजनीतिक संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से संबंधित चिंताओं को रेखांकित करते हुए बताया है कि डेटा आधारित राजनीतिक संचार में नागरिकों की जानकारी के उपयोग, सहमति और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।[xvii]। इसलिए राजनीतिक डिजिटल संचार में डेटा सुरक्षा और नागरिकों की निजता का संरक्षण आवश्यक है।
5. **डिजिटल असमानता–** डिजिटल मीडिया की उपलब्धता समाज के सभी वर्गों में समान नहीं है। इंटरनेट सुविधा, उपकरणों की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, डिजिटल कौशल तथा भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर के कारण नागरिकों की डिजिटल पहुँच अलग–अलग हो सकती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम डिजिटल साक्षरता वाले नागरिकों की राजनीतिक सूचना तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित हो सकती है। इससे डिजिटल जनमत व्यापक समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व न कर पाए, ऐसी संभावना रहती है। नॉरिस, पिप्पा ने डिजिटल विभाजन की चर्चा करते हुए बताया है कि तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता सामाजिक

और राजनीतिक सहभागिता में असमानता को जन्म दे सकती है।[xviii] भारतीय संदर्भ में डिजिटल असमानता को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतांत्रिक जनमत निर्माण में सभी सामाजिक वर्गों की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

6. **सामाजिक मीडिया पर राजनीतिक प्रचार एवं दुष्प्रचार–** सामाजिक मीडिया राजनीतिक प्रचार के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराता है, लेकिन इसी क्षमता का उपयोग दुष्प्रचार के लिए भी किया जा सकता है। राजनीतिक दलों, समर्थक समूहों अथवा अन्य संगठित समूहों द्वारा चयनित सूचनाओं को व्यापक स्तर पर प्रसारित करके नागरिकों की धारणाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। भावनात्मक सामग्री, आधी–अधूरी जानकारी और भ्रामक दावों का लगातार प्रसार राजनीतिक जनमत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए डिजिटल राजनीतिक संचार में पारदर्शिता, तथ्य–जाँच और नागरिकों की आलोचनात्मक सूचना–समझ आवश्यक है। भारत में सामाजिक मीडिया के राजनीतिक उपयोग पर अध्ययन करते हुए शर्मा, नेलम तथा शिवकुमार, गायत्री ने राजनीतिक संचार में सामाजिक मीडिया की बढ़ती भूमिका के साथ उससे जुड़े ध्रुवीकरण और सूचना संबंधी प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।[xix] अतः डिजिटल मीडिया को लोकतांत्रिक जनमत निर्माण का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए सूचना की सत्यता, नागरिकों की डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा और जिम्मेदार राजनीतिक संचार को समान महत्व देना आवश्यक है।

भारतीय लोकतंत्र पर डिजिटल मीडिया का प्रभाव

1. **लोकतांत्रिक सहभागिता–** डिजिटल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता के स्वरूप को व्यापक और बहुआयामी बनाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा, सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया तथा सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी भी लोकतांत्रिक सहभागिता के महत्वपूर्ण रूप हैं। डिजिटल माध्यमों ने नागरिकों को इन गतिविधियों में अपेक्षाकृत सरलता से शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। नागरिक राजनीतिक दलों और नेताओं के विचारों को जान सकते हैं, सार्वजनिक नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। इससे राजनीतिक सहभागिता अधिक निरंतर और संवादात्मक बनी है। विशेष रूप से युवाओं के लिए डिजिटल मंच राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर सामने आए हैं।
2. **नागरिक सशक्तिकरण–** डिजिटल मीडिया नागरिकों को सूचना और अभिव्यक्ति के साधन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तिकरण में योगदान करता है। नागरिकों को सरकारी योजनाओं, नीतियों, अधिकारों और सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे विभिन्न डिजिटल स्रोतों के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों तथा समस्याओं को व्यापक स्तर पर सामने रख सकते हैं। डिजिटल मंचों के माध्यम से नागरिक अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सामूहिक मुद्दे का रूप भी दे सकते हैं। इससे शासन व्यवस्था में नागरिकों की आवाज अधिक स्पष्ट रूप से सामने आने की संभावना बढ़ती है। डिजिटल मीडिया नागरिकों को केवल सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति न बनाकर सूचना के निर्माण और प्रसार में भी सहभागी बनाता है। इस प्रकार यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।
3. **राजनीतिक पारदर्शिता–** डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। सरकारी संस्थाएँ अपनी नीतियों, योजनाओं, निर्णयों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएँ डिजिटल माध्यमों द्वारा नागरिकों तक पहुँचा सकती हैं। राजनीतिक नेता और जनप्रतिनिधि भी अपनी गतिविधियों तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी सीधे जनता के सामने रख सकते हैं। इससे नागरिकों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर निगरानी रखना अपेक्षाकृत आसान हुआ है। इसके अतिरिक्त डिजिटल माध्यमों पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ राजनीतिक संस्थाओं को नागरिकों की अपेक्षाओं और समस्याओं से अवगत कराने में सहायता कर सकती हैं। हालांकि पारदर्शिता तभी प्रभावी हो सकती है जब उपलब्ध सूचना सही, पूर्ण, समयबद्ध और आसानी से समझने योग्य हो। केवल बड़ी मात्रा में सूचना उपलब्ध होना अपने आप में वास्तविक पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करता।
4. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता–** डिजिटल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक विस्तृत सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराया है। नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा विभिन्न मुद्दों पर समर्थन या असहमति दर्ज कर सकते हैं। इससे उन समूहों और व्यक्तियों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है जिन्हें पारंपरिक सार्वजनिक मंचों पर पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता था। राजनीतिक बहस में विविध विचारों की उपस्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सहभागी बना सकती है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदार अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी जुड़ी हुई है। झूठी सूचना, घृणात्मक सामग्री, व्यक्तिगत आक्षेप और जानबूझकर फैलाया गया दुष्प्रचार डिजिटल अभिव्यक्ति के सकारात्मक पक्ष को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल माध्यमों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के बीच संतुलन आवश्यक है।

5. **लोकतांत्रिक विमर्श की बदलती प्रकृति–** डिजिटल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक विमर्श की प्रकृति को भी बदल दिया है। पहले राजनीतिक बहस मुख्यतः संसद, राजनीतिक सभाओं, समाचार–पत्रों, टेलीविजन और अन्य पारंपरिक सार्वजनिक मंचों तक सीमित रहती थी। अब राजनीतिक विमर्श सामाजिक माध्यमों, ऑनलाइन समाचार मंचों, वीडियो सामग्री तथा विभिन्न डिजिटल चर्चा मंचों तक विस्तारित हो गया है। नागरिक राजनीतिक मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं और किसी घटना को व्यापक सार्वजनिक चर्चा का विषय बना सकते हैं। इससे राजनीतिक विमर्श अधिक त्वरित और सहभागी हुआ है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों पर विचारों की अत्यधिक विविधता, भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। अतः भारतीय लोकतंत्र पर डिजिटल मीडिया का प्रभाव बहुआयामी है। यह नागरिक सहभागिता, सशक्तिकरण, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ सूचना की विश्वसनीयता, जिम्मेदार अभिव्यक्ति और समावेशी डिजिटल पहुँच जैसी आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करना होगा।

निष्कर्ष

डिजिटल मीडिया ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जनमत निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किया है। इसने राजनीतिक सूचना के प्रसार को अधिक तीव्र, व्यापक और सहभागी बनाया है तथा नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने के नए अवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल माध्यमों के द्वारा नागरिक राजनीतिक दलों, नेताओं, सरकारी नीतियों और समकालीन राजनीतिक मुद्दों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने के साथ–साथ अपनी प्रतिक्रियाएँ और विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संचार अब केवल राजनीतिक संस्थाओं से नागरिकों की ओर सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो गई है। डिजिटल मीडिया ने विशेष रूप से युवाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विमर्श के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल मीडिया राजनीतिक जनमत निर्माण को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। यह नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, राजनीतिक मुद्दों को व्यापक सार्वजनिक चर्चा में लाने, राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं और विचारों को व्यापक स्तर पर सामने रख सकते हैं, जिससे राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता की संभावनाएँ बढ़ती हैं। साथ ही, डिजिटल माध्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तार देते हुए विभिन्न सामाजिक समूहों को राजनीतिक विमर्श में शामिल होने का अवसर प्रदान करते हैं।

हालाँकि डिजिटल मीडिया के प्रभाव को केवल सकारात्मक रूप में नहीं देखा जा सकता। फर्जी समाचार, भ्रामक सूचनाएँ, राजनीतिक ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार, निजता संबंधी चिंताएँ और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियाँ लोकतांत्रिक जनमत की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि नागरिक डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और राजनीतिक संस्थाएँ तथा मीडिया संगठन जिम्मेदार एवं पारदर्शी संचार को बढ़ावा दें। अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है, लेकिन इसका लोकतांत्रिक प्रभाव सूचना की विश्वसनीयता, डिजिटल साक्षरता, जिम्मेदार अभिव्यक्ति और समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

i बीजू पी. आर., पॉलिटिकल इंटरनेटः स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, टेलर एंड फ्रांसिस, लंदन, 2016, पृ. 60–86

ii चोपड़ा, शालिनी, द बिग कनेक्टः पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, रैंडम हाउस इंडिया, नई दिल्ली, 2014, पृ. 24दृ36, 99–103

iii मोइनुद्दीन, शेख, द पॉलिटिकल ट्विटरस्पियर इन इंडिया, स्प्रिंगर, चाम, 2019, पृ. 61–90

iv लाल, अनिकेत, इंडिया सोशल, हैशेट इंडिया, नई दिल्ली, 2017

v सेठ, सुरेश, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 45–67

vi चोपड़ा, शालिनी, द बिग कनेक्टः पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, रैंडम हाउस इंडिया, नई दिल्ली, 2014, पृ. 72–94

vii मोइनुद्दीन, शेख, द पॉलिटिकल ट्विटरस्पियर इन इंडिया, स्प्रिंगर, चाम, 2019, पृ. 61–90

viii नयाजी, तबरेज अहमद, कुमार, अनूप एवं सेमेटको, हॉली ए., सोशल मीडिया, पॉलिटिकल कैम्पेनिंग एंड द 2014 इंडियन इलेक्शन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस एंजिल्स, 2016, पृ. 3992–4013

ix कानूंगो, नीना तलवार, इंडियन इलेक्शंस एंड सोशल मीडियाः द वर्चुअल पब्लिक स्फीयर, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नई दिल्ली, 2015, पृ. 59–74

x चोपड़ा, शालिनी, द बिग कनेक्टः पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, रैंडम हाउस इंडिया, नई दिल्ली, 2014, पृ. 72–94

xi नयाजी, तबरेज अहमद, कुमार, अनूप एवं सेमेटको, हॉली ए., सोशल मीडिया, पॉलिटिकल कैम्पेनिंग एंड द 2014 इंडियन इलेक्शन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस एंजिल्स, 2016, पृ. 3992–4013

xii मोइनुद्दीन, शेख, द पॉलिटिकल ट्विटरस्पियर इन इंडिया, स्प्रिंगर, चाम, 2019, पृ. 61–90

xiii उदूपा, साहना, वेंकटरमन, श्रीराम एवं खान, आसिम, हैशटैग पॉलिटिक्सः डिजिटल मीडिया, हैशटैग और इंडियन पब्लिक स्फीयर, सोशल मीडिया. सोसाइटी, लंदन, 2020, पृ. 1–12

xiv वार्डल, क्लेयर एवं डेराखशन, होसैन, इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डरः टुवर्ड्स ऐन इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, काउंसिल ऑफ यूरोप, स्ट्रासबर्ग, 2017, पृ. 5–20

xv सनस्टीन, कैस आर., रुरिपब्लिकः डिवाइडेड डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, 2017, पृ. 59–83

xvi वार्डल, क्लेयर एवं डेराखशन, होसैन, इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डरः टुवर्ड्स ऐन इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, काउंसिल ऑफ यूरोप, स्ट्रासबर्ग, 2017, पृ. 20–25

xvii कैडवालाडर, कैरोल, द ग्रेट हैकः कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड द ब्रेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पेगासस बुक्स, नई दिल्ली, 2019, पृ. 91–115

xviii नॉरिस, पिप्पा, डिजिटल डिवाइडः सिविक एंगेजमेंट, इनफॉर्मेशन पॉवर्टी एंड द इंटरनेट वर्ल्डवाइड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2001, पृ. 3–26

xix शर्मा, नेलम एवं शिवकुमार, गायत्री, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन इंडिया, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2023, पृ. 1–18